राज्यों में खनिजों का दोहन

3933. **श्री राम नरेश यादव:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में दोहन किये गए खनिजों का ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान कुल कितनी कीमत के खनिजों का दोहन किया गया;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान तीनों राज्यों द्वारा कितने-कितने मूल्य के खनिजों का वर्ष-वार निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त राज्यों द्वारा इस निर्यात से कितना-कितना लाभ अर्जित किया गया?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान खनिजों के विदोहन की स्थिति इस प्रकार है:—

बिहार: 1990-91 और 1991-92 के दौरान बिहार में निकाले गए खनिजों में कोयला, बाक्साइट, तांबा अयस्क, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, डोलोमाइट, केल्सपार, फायरक्ले, ग्रेफाइट, काओलिन, कायनाइट, चूना पत्थर, अभ्रक, ओकर, पायराइट, क्वार्टज, क्वार्टजाइट; सिलिका बालू और स्टीटाइट शामिल हैं। 1990-91 और 1991-92 के दौरान बिहार में उत्पादित खनिजों का मूल्य क्रमशः 2198 करोड़ रु० और 2354 करोड़ रु० रहा है।

मध्य प्रदेश: 1990-91 और 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में निकाले गए खनिजों में कोयला, बाक्साइट, तांबा अयस्क, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, टिन, फास्फोराइट, बैराइट कैल्साइट क्ले, कोरंडम, हीरा, डायस्पोर, डोलोमाइट, फेल्सापार, फायरक्ले, काओलिन, चूना पत्थर, ओकर, पायरोफ्लाइट क्वार्टजाइट, सिलिका बालू स्लेट, स्टीटाइट और लेटराइट शामिल हैं। 1990-91 और 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में उत्पादित खनिजों का मूल्य क्रमशः 2050 करोड़ रु० और 2296 करोड़ रु० रहा है।

उत्तर प्रदेश: 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में निकाले गए खनिजों में कोयला, फास्फोराइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, पाइरोफ्लाइट, सिलिका बालू और स्टीटाइट शामिल हैं। 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में उत्पादित खनिजों का मूल्य क्रमशः 231 करोड़ रु० और 303 करोड़ रु० रहा है।

(ख) और (ग) निर्यात आंकड़े पूरे देश के लिए और राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। 1990-91 और 1991-92 के दौरान देश खनिजों और अयस्कों के समग्र निर्यातों का अनुमानित मूल्य क्रमश 1739.71 करोड़ रु० और 2281.08 करोड़ रु० है।

हिन्दुस्तान कापर लि० को कच्चे माल की आपूर्ति

3934. **श्री गया सिंह:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान कापर लि० को कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फैक्टरी के समीप दो खानों का विस्तार कार्य रोक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान कापर लि० की खेतड़ी (राजस्थान) और घाटशिला (बिहार) में खान भी और स्मैल्टर भी है। हिन्दुस्तान कापर लि० का आठवीं योजना के दौरान धन की उपलब्धता के अनुसार उक्त दोनों स्थानों पर निम्नलिखित परियोजनाएं आरंभ करने का प्रस्ताव है:—

खेतड़ी बनवास खान का 2,000 टन दैनिक अयस्क क्षमता तक विकास।

घाटशिला

1. केन्डाडीह खान का 200 टन दैनिक से 700 टन दैनिक अयस्क तक विस्तार।

2. राखा खान का 1000 टन दैनिक से 2000 टन दैनिक अयस्क तक विस्तार।

3. धोबानी खान (नई खान) 500 टन दैनिक अयस्क क्षमता।

4. चापरी-सिधेश्वरी खान (नई खान तथा सांद्रक संयंत्र)।

Public Sector Plan Outlay for Steel

3935. SHRI DIPEN GHOSH: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether in view of the reduction in the public sector plan outlay for steel from the originally proposed level of Rs. 24,000 crore to Rs. 14,000 crore Government expect the gap to be bridged by the private sector since the industry has been deregulated; and

(b) what is the response from the private sector including foreign companies?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) Increased production in the private sector is expected to help in bridging the demand and supply gap in steel.

(b) The large number of Industrial Entrepreneurs' Memoranda filed for new steel projects and expansion of existing capacities is indicative of the interest shown by the private sector to invest in the steel industry. The State Governments of Orissa and Karnataka have proposed to Implement integrated steel plants in the joint sector. Interest has also been shown by some private sector companies to set up large integrated steel plants. A number of sponge iron/-pig iron plants are under implementation in the private sector.

Ship Breaking Yards

3936. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) what is the policy of Government regarding scheme for setting up ship breaking yards in the country and details of ongoing schemes with their performance profile, State-wise, for the last five years;

(b) what are the schemes in operations during the Eighth Five Year Plan and expansion of schemes proposed on the Western coast of Maharashtra in partiuclar; and

(c) the details of steps taken/proposed to be taken to revive the working of ship breaking activities on Western coast of Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) to (c) The State Governments take up development of ship breaking yards in their respective States. Information is being collected from the concerned State Governments and will be laid on the Table of the House.

Duty on Import of Pig Iron

3937. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) how the average prices of Pig iron from indigenous resources compare with that of the imported pig iron, following the decontrol of pig iron;

(b) whether in order to narrow down the difference between the prices of imported raw material and the indigenous pig iron, government have considered the question of reducing the custom duty thereon;

(c) if so, what decision has since been taken in the matter; and

(d) what are the steps taken by Government to fulfil the requirement of Pig iron by different industries?

THE MINISTER OF STATE OF THE' MINISTRY OF STEEL (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) In the month of November, 1992 the open market prices of pig iron inclusive of taxes were ranging between Rs. 5900 and Rs. 6700 per tonne. The landed cost of imported pig iron was about Rs. 7200 per tonne.

(b) to (d) In order to enable different industries to meet their requirements, pig iron has been made freely importable. Import duty on pig iron was also reduced from 55% to 35% *ad valorem* in January, 1992.

Government have also taken various steps to encourage production of pig iron in the private sector. These include exemption of the pig iron industry from the provisions of compulsory licensing, its identification as a high priority industry for foreign investment and dispensing with the price and distribution regulation of different iron and steel items including pig iron.

Modernisation of Rourkela Steel Plant

3938. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Metallurgical and Engineering Consultants (India) Limited has been awarding contracts to private parties, ignoring the claims of public sector with